International Journal of Applied Research 2020; 6(2): 356-358

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2020; 6(2): 356-358
www.allresearchjournal.com
Received: 28-12-2019
Accepted: 02-01-2020

डॉ० किरण कुमारी
असिस्टेंट प्रोफेसर, मिल्लत षिक्षण प्रषिक्षण महाविद्यालय, मधुबनी, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ० किरण कुमारी
असिस्टेंट प्रोफेसर, मिल्लत षिक्षण प्रषिक्षण महाविद्यालय, मधुबनी, बिहार, भारत

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता : चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

डॉ० किरण कुमारी

सारांश
भारत अब विश्व के अग्रणी देशों में सम्मिलित हो चुका है। यह विश्व की बड़ी आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। भारत निकट भविष्य में ही सम्पूर्ण विश्व को प्रशिक्षित मानव संसाधनों की आपूर्ति करने वाला देश होगा। कृषि, उधोग व सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास के साथ–साथ गरीबी निवारण, रोजगार सृजन व ज्ञान आधारित समाज की संरचना एवं चरित्रवान कुशल नागरिकों के निर्माण के लिए देश में शिक्षा एवं प्रशिक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है जो शिक्षा जगत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस दिशा में केन्द्र सरकार के द्वारा नयी शिक्षा नीति लायी गयी है जो एक सराहनीय कदम है परन्तु नयी शिक्षा नीति को व्यावहारिक पटल पर सार्थक बनाना भी एक चुनौती है।
शिक्षा का परिमाणात्मक विकास विगत वर्षों में तेजी से हुआ है परन्तु गुणात्मक विकास में ह्रास हुआ है, जो चिन्तनीय है। आज भी शिक्षा पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है। अंग्रेजों ने शिक्षा को अपने हित के लिए इस्तेमाल किया। उनका उद्देश्य भारत में एक ऐसा शिक्षित वर्ग पैदा करना था जो औपनिवेशक शासन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक हो। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य मात्र बाबूओं का निर्माण करना था। फलस्वरूप शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती गयी और आज शिक्षित बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गयी है। आवश्यकता है, शिक्षा की गुणवत्ता के विकास की, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है परन्तु, गुणवत्ता में सुधार की संभावनाओं का अभाव नहीं है। शिक्षा मानवीय मूल्यों, तकनीकी ज्ञान एवं अद्यमिता के विकास में सार्थक पहल कर सकता है जिसकी अपार संभावनाएँ हैं।

मुख्य भाब्द : शिक्षा, परिमाणात्मगक विकास, गुणात्मक विकास, प्रशिक्षण, वैश्विक, चुनौतियाँ, संभावनाएँ।

प्रस्तावनाः
शिक्षा मानक संसाधन के विकास का मुख्य आधार है। विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में सूचीबद्ध भारत शिक्षा के विकास के कतार में बहुत पीछे है। शिक्षा की गुणवत्ता में अभाव के कारण भारतीय छात्र विश्व की मांग के अनुरूप नहीं बन पाते हैं, जो भारतीय शिक्षा के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। देश के सभी विश्वविद्यालयों के परिसर में उच्च शिक्षा में दाखिला लेने को उत्सुक छात्रों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। विगत वर्षों में बारहवीं कक्षा के परिणाम आते ही उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाले छात्रों की भीड़ बढ़ जाती है। यह शिक्षा के परिमाणात्मक विकास का सूचक है। यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान की 2013 की रिर्पोट के अनुसार उच्च शिक्षा में 1970 में दुनियाभर में कुल नामांकन जहाँ 32ण्6 मिलियन था, 2011 में 182ण्2 मिलियन पहुँच गया। पूर्वी और दक्षिणी एशिया के देशों की भागीदारी इस नामांकन में 46ः रही। अभी उम्मीद की जा रही है कि भारत सहित दक्षिण एशिया और मध्य अफ्रीका में उच्च शिक्षा का विस्तार 2030 तक तीव्र गति से होगी।
भारत सहित अन्य एशियाई देशों ने उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग और शिक्षा संस्थानों ने उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग और शिक्षा संस्थानों की कमी को देखते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया। विगत वर्षों में भारत में जहाँ कुछ नये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं प्रादेशिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, वहीं निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी सरल किया गया। सरकारी विश्वविद्यालयों को स्ववित्त पोषित कोर्स चलाने की अनुमति को संख्या तो बढ़ी परन्तु छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या कम होती गयी। कुशल शिक्षकों का अभाव हो गया। प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों की क्रियाशिलता में कमी आती गयी। हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा में नकल की संस्कृति और फर्जी डिग्री के कारोबार में वृद्धि हुई। पाठ्य–क्रमों में 21 वीं शदी के सामाजिक–आर्थिक दूरी को कम कर सके । युवाओं को बिना भेदभाव के रोजगार और शोध से जोड़ने वाली उच्च शिक्षा का मॉडल, आज की जरूरत भी है और हमारे भविष्य की योजना की कसौटी भी। निश्चय ही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में आवश्यक सुधार हमारी चुनौती है। लेकिन यह भी सच है कि इस वैश्विक वातावरण में सुधार की अपार संभावनाएँ भी हैं।

भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति :

भारत में आधुनिक उच्च शिक्षा अंग्रेजों की देन है। इसके जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता हैं। उनका उद्देश्य भारत में एक ऐसा शिक्षित वर्ग पैदा करना था जो औपनिवेशक शासन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक हो। सन् 1916 में भारत में पाँच विश्वविद्यालय थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का लक्ष्य ईसाई धर्म और अंग्रेजी राज्य की नींव मजबूत करना था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने शिक्षा की प्रगति की और ध्यान दिया। 14 नवम्बर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इसका उद्येश्य विधार्थियों में अनुरूप एवं वैश्विक मांग आलोक में परिवर्तन नहीं किए गये थे। पाठ्य–क्रम के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पहलु ऐसी नहीं है कि छात्रों में तकनीकी ज्ञान, उद्यमीय कौशल एवं नैतिक मूल्यों का पर्याप्त विकास हो सके ताकि वे राष्ट्र एवं विश्व के बहुआयामी विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके।

हमारे देश में आई0 आई0 टी0 और आई0 आई0 एम0 जैसे संस्थान गुणवत्ता के पर्याय माने जाते हैं, लेकिन उन तक पहुँचना आसान नहीं है। वैसे तो देश में 800 से अधिक विश्वविद्यालय है लेकिन गुणवत्ता वाली शिक्षण संस्थाओं का बहुत अभाव है। उच्च शिक्षा की शिक्षा बजट में भागीदारी बढ़ी है लेकिन छात्रों की बढ़ती संख्या के अनुपात में आर्थिक संसाधन एवं शिक्षकों तथा प्रशिक्षकों की डिग्री लेकर, बड़ी संख्या में छात्र बेरोजगार घूम रहे है। भारत में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बनना चाहिए जो दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करने में सफल हो और देश में नेतृत्व, संस्कृति एवं व्यक्तित्व का विकास कर सके। सन् 1951 में हमारे देश में 798 महाविद्यालय एवं 27 विश्वविद्यालय थे जिनकी संख्याा बढ़कर 2000 में 10ए555 महाविद्यालय व 221 विश्वविद्यालय हो गयी। इस प्रकार विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

सन् 1854 में चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी राज्य में शिक्षा का उद्देश्य राज्य सेवा हेतु ईमानदार सेवक तैयार करना बताया। सन् 1883 में विलियम हण्टर ने शिक्षा को जिला वार्ड और म्युनिस्पलिटी के अधीन करने की सिफारिश की । सन् 1917 में उच्च शिक्षा के दोषों की जाँच के लिए सैडलर कमीशन बनाया गया। सन् 1944 में सार्जेंट कमीशन ने स्नातक डिग्री कोर्स तीन वर्षों में पूरा करने की अनुशंसाा की । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 1948 में डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनाई गई कमीटी ने अवकाश, वेतन, अध्ययन स्तर व विषयों के संदर्भ में अपने विचार दिये। सन् 1966 में शिक्षा में सुधार हेतु कोठारी आयोग बनाया गया जिसने उच्च शिक्षा के लिए निर्धारित करने एवं इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन के सुझाव दिये। सन् 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा 1992 में शिक्षा में सुधार हेतु नई शिक्षा नीति बनायी गयी। अभी–अभी केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा में व्यापक सुधार हेतु नयी शिक्षा निति 2020 लायी गयी है। इस प्रकार विभिन्न समितियों एवं आयोगों द्वारा समय–समय पर उच्च शिक्षा के समक्ष खड़ी चुनौतियों की और ध्यान आकृष्ट किया गया और आवश्यक सुझाव दिये गये। इसके बावजूद भी भारत में शिक्षा व्यवस्था की रूपरेखा वही है जो अंग्रेजों ने पढ़े–लिखे कलर्क और शासकीय सेवक प्राप्त करने के लिये यहाँ प्रारम्भ की थी। यद्यपि समितियों एवं आयोगों के रिपोर्टो में बार–बार इन बातों पर बल दिया गया कि हमारी शिक्षा देश की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए परन्तु न तो शिक्षा पद्धति का भारतीयकरण हुआ और न ही शिक्षा दैनिक जीवन में उपयोगी बन पायी। न ही अर्थोत्पादक बन सका और न ही ईमानदार नागरिक बना सका। वस्तुतः उच्च शिक्षा देश के नागरिक में प्रजातंत्रीय भावनाओं, सामाजिक समरसताओं, नैतिक मूल्यों, उद्यमीय कुशलताओं के विकास एवं वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक तथा तकनीकी ज्ञान प्रदान करने में असफल रही हैं।

चुनौतियाँ :

भारत में उच्च शिक्षा का विकास अनियोजित रहा है। परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर शिक्षास्तर में गिरावट आयी है, वहीं छात्रों में ज्ञानोर्जन एवं चरित्र निर्माण की अभिलाषा नष्ट हुई है। शिक्षित व्यक्तियों के समक्ष बेरोजगारी की विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है। हमारी उच्च शिक्षा ज्ञानोन्मुखी एवं नैतिकता उन्मुखी नहीं हैं। मात्र डिग्री उन्मुखी है। इसका स्वरूप शिक्षक केन्द्रित व परीक्षोन्मुखी है जो सिर्फ डिग्री बॉटता है। इसके समक्ष कई चुनौतियाँ है जिसमें प्रममुख निम्नलिखित है :–

- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योग्य शिक्षकों की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है। न्ळब् के अनुसार, कुल स्वीकृत शिक्षण पदों में से 35ः प्रोफेसर के पद 46ः एसोसिएट प्रोफेसर के पद और 26ः सहायक प्रोफेसर के पद रिक्त हैं।
- उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एक बहुज बड़ी चुनौती है। टॉप 200 विश्व रैंकिंग में भारतीय शिक्षण संस्थानों को स्थान नहीं मिल पाता है।
- शिक्षा में सुधार हेतु बने रोडमैप की व्यावहारिक पटल पर बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है।
- उच्च शिक्षा में नामांकन का एक बड़ा हिस्सा राज्य विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों से आता है, जबकि इन राज्य विश्वविद्यालयों को अपेक्षाकृत बहुत कम अनुदान प्राप्त होता है। न्ळब् के बजट का लगभग 65ः केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और उनके कॉलेजों को मिलता है और शेष 35ः मात्र राज्य विश्वविद्यालयों और उनके सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या अधिक है।
- तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का अभाव हमारे सामने एक चुनौती है, क्योंकि कोरिया में 95ः , चीन में 80ः , जर्मनी में 80ः , अस्ट्रेलिया में 70ः , ब्रिटेन में 60ः युवक तकनीकी शिक्षा से लैस है, जबकि भारत में तकनीकी शिक्षा पाने वाले युवाओं का प्रतिशत मात्र 2ण्2 है।
- देश की आबादी में प्रतिवर्ष 2ण्8 करोड़ युवा लेवर फोर्स के रूप में उधोग में जाते हैं जिसमें मात्र 25 लाख की कुशल होते हैं।
- भारत में निजी संस्थानों और विश्वविद्यालयों का कोई मानक स्तर नहीं है।
- अधिकांश महाविद्यालयों में पर्याप्त बुनियादी ढ़ाचें नहीं है।
- भारत में ग्रास एनरोलमेंट ;ळम्द्ध मात्र 12ः है जो वैश्विक औसत से काफी कम है।
- छात्रों में नैतिक मूल्यों का समावेश कैसे हो, छात्रों को नैतिक आदर्शों के प्रति आस्था कैसे जगे एवं ज्ञान, व्यवहार, जीवन शैली एवं आचरण में सामंजस्य कैसे बने? यह एक बड़ी चुनौती शिक्षा व्यवस्था के समक्ष है।
- उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इसकी गुणवत्ता बढ़ायी जा सकती है। इससे अंतर सांस्कृतिक संवाद व अंतराष्ट्रीय शान्ति को भी बढ़ावा मिल सकता है, इसलिए भारतीय उच्च शिक्षा में सुधार प्रक्रिया को अंतराष्ट्रीय दृष्टिकोण के मद्देनजर विश्वस्तरीय मापदंडों के अनुकूल बनाने व परखने की आवश्यकता है जो भारतीय उच्च शिक्षा के समक्ष एक बड़ी चुनौती है।
- उच्च शिक्षा की गुणवत्ता विकास हेतु तीन सकारों स्केल, स्किल एवं स्पीड पर बल देने की आवश्यकता है। स्केल, स्किल एवं स्पीड को शिक्षा जगत में सार्थक बनाना भी एक चुनौती है।
- वर्त्तमान में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों की जबावदेही सुनिश्चित कैसे की जाय? यह भी एक चुनौती है।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु न्ळ्ब् की नयी पहल :

देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता में सुधार के लिए न्ळ्ब् ने नई 12 सूत्रीय गाइड लाइन तैयार की है, जिसमें उन सभी पहलुओं को शामिल किया गया है जो किसी भी संस्थान के लिए जरूरी होता है। ये 12 बिन्दु निम्नलिखित हैं :–

1. छात्रों के लिए प्रेरण कार्य – क्रम
2. शिक्षा परिणाम आधारित पाठ्य – क्रम रूप रेखा (एलओसीएफ) में संशोधन ;स्मंतदपदह वनजबवउमे इंमक बनततपबनसनउ थ्तंउमूवता ;स्व्थ्द्ध तमअपेपवदद्ध
3. प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया के लिए आई सी टी आधारित शिक्षा उपकरणों का उपयोग
4. छात्रों के लिए जीवन कौशल
5. प्रत्येक संस्थान को समाज और उद्योग से जुड़ाव
6. छात्र कैरियर प्रगति और पूर्व छात्र नेटवर्क
7. संकाय प्रेरण कार्य–क्रम
8. संकाय द्वारा गुणवत्ता अनुसंधान को बढ़ावा देना और नए ज्ञान का सृजन
9. परामर्श
10. सतत् उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मानवमूल्यों और व्यावसायिक आचार नीति के लिए दिशा – निर्देश
11. सतत् उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पर्यावरण अनुकूलन और परिसर विकास की रूप रेखा
12. मूल्यांकन सुधार

संभावनाएँ :

भारतीय उच्च शिक्षा का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। सरकार द्वारा भारतीय निजी संस्थानों, उद्योगों और विदेशी संस्थानों से भागीदारी की जा रही है। भारतीय जनसांख्यिकी और इसकी विविधता के अनुरूप शिक्षा को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि भारत को विकसित देश में शुमार किया जा सके। पिक्की और अर्नेस्ट एंड यंग को एक संयुक्त अध्ययन ''नए सच नयी संभावनाएँ : भारतीय उच्च शिक्षा का बदलता चेहरा'' में भारतीय उच्च शिक्षा में भविष्य की दशा और दिशा निर्धारित करने वाले कारकों पर रोशनी डाली गई है।

रिपोर्ट में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे खर्च विधार्थियों की नयी श्रेणी, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं के लिए भुगतान करने के इच्छुकों की बड़ी संख्या, ग्लोबल शिक्षा की बढ़ती मांग, रोजगारोंन्मुखी शिक्षा की मांग, आदि कारकों पर चर्चा की गयी है। अध्ययन में यह बताया गया है कि अभी भारत में एक कराड़ 36 लाख छात्र उच्च शिक्षा में अध्ययन कर रहे है। विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु जाने वाले छात्रों में अधिकांश भारतीय है। इस प्रकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त संभावनाएँ है। आवश्यकता है उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की और इस हेतु सरकार के दृढ़ ईच्छा शक्ति एवं ईमानदार प्रयास की जरूरत है। इस हेतु सरकार, संस्थान, शिक्षक, छात्र में समन्वय की आवश्यकता तथा सभी के सहयोग की आवश्यकता है।

निष्कर्ष :

यदि हम भविष्य में भयंकर विपत्ति से घिरना नहीं चाहते तो हमें उच्च शिक्षा व अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूत करना होगा। वर्त्तमान शिक्षा द्वारा दोनों को मजबूत करना होगा। वर्त्तमान शिक्षा व्यवस्था की स्थिति सुधार की अपेक्षा रखती है, परन्तु सुधार हेतु कर्त्तव्यबोध का अभाव है।

वास्तव में समस्या, साधन या संख्या की नहीं अपितु वातावरण एवं व्यवस्था की है। शिक्षा का परिणाम 15.20 वर्ष बाद सामने आता है 20 वर्ष पहले का परिणाम आज हमारे सामने है। आज आवश्यकता है ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्थक हो सके, समाज तथा देश के विकास में अपनी भागीदारी दे सके, छात्रों को रोजगार एवं स्वच्छ चरित्र प्रदान कर सके। इस हेतु नयी शिक्षा नीति 2020 एवं न्ळ्ब् का 12 सूत्रीय कार्य–क्रम सराहनीय है।

निश्चय ही भारत अपने मौलिक विचारों, आदर्शों, तकनीकों एवं वैश्विक विकासों, मांगों से समन्वय स्थापित कर, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का विकास करने में सफल होगा।

संदर्भ :

1. अग्रवाल. पी. (2006), ''भारत में उच्च शिक्षा बदलाव की आवश्यकत,'' सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 83।
2. अखण्ड ज्योति, अक्टूबर 2018, मुद्रक एवं प्रकाशकः अखण्ड ज्योती संस्थान, मथुरा।
3. युग निर्माण योजना, फरवरी 2020, मुद्रक एवं प्रकाशक : युग निर्माण योजना ट्रस्ट, मथुरा।
4. शैक्षिक मंथन, दिसंबर 2009, मुद्रक एवं प्रकाशकः अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ।
5. शैक्षिक मंथन, अक्टूबर 2008, मुद्रक एवं प्रकाशक : अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंध।
6. शैक्षिक प्रबंधन – डॉ0 दीप्ती शर्मा।
7. नरेन्द्र सिंह व सीमा देवी : भूमण्डलीकरण के दौर में शिक्षा पर प्रभाव, कुरूक्षेत्र सितम्बर 2004 ग्रामीण विकास मन्त्रालय।